



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14022020-216147
CG-DL-E-14022020-216147

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39]
No. 39]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 7, 2020/माघ 18, 1941
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 7, 2020/MAGHA 18, 1941

(वाणिज्य विभाग)

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच की शुरुआत की अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2020

मामला सं. एसएसआर- 04/2020

विषय: कोरिया गणराज्य से एक्रीलोनाइट्राइल बुटाडीन रबड़ के आयातों के संबंध में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच ।

फा. सं. 7/5/2020-डीजीटीआर.—1. मैसर्स एंफोटेक्स इंडस्ट्रीज लिमि. (जिसे यहां "आवेदक" कहा गया है) ने समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 (जिसे यहां "नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसरण में कोरिया गणराज्य (जिसे यहां "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'एक्रीलोनाइट्राइल बुटाडीन रबड़' (जिसे यहां "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद या " पीयूसी" या एनबीआर कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा के लिए घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे यहां "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है

- आवेदक ने संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने तथा घरेलू उद्योग को उसके परिणामस्वरूप क्षति होने की संभावना का आरोप लगाया है और संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने और उसकी समीक्षा करने का अनुरोध किया है ।

पृष्ठभूमि

3. कोरिया गणराज्य और जर्मनी से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में मूल जांच प्राधिकारी द्वारा दिनांक 15 मार्च 1996 की अधिसूचना सं. 9/1/95- एडीडी के तहत शुरु की गई थी। प्राधिकारी द्वारा दिनांक 30 दिसंबर 1996 को प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए गए थे जिसमें कोरिया गणराज्य और जर्मनी के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'एक्रीलोनाइट्राइल बुटाडीन रबड़ (एनबीआर)' के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई थी। प्राधिकारी ने दिनांक 17 जुलाई 1997 को अपने अन्तिम जांच परिणाम अधिसूचित किए जिसमें कोरिया गणराज्य और जर्मनी के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'एक्रीलोनाइट्राइल बुटाडीन रबड़ (एनबीआर)' के आयातों पर निश्चित पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी। संबद्ध वस्तुओं पर निश्चित पाटनरोधी शुल्क दिनांक 30 जुलाई 1997 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 62/1997- सीमाशुल्क के तहत लगाया गया था।
4. प्राधिकारी ने कोरिया गणराज्य और जर्मनी के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'एक्रीलोनाइट्राइल बुटाडीन रबड़ (एनबीआर)' पर अन्तिम पाटनरोधी शुल्क जारी रखने के मामले पर एक निर्णायक समीक्षा जांच शुरु की थी और दिनांक 21 सितम्बर 2002 की अधिसूचना सं. 50/1/2000 के तहत संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चित पाटनरोधी शुल्क लगाना जारी रखने की सिफारिश की है। दिनांक 10 अक्टूबर 2002 की अधिसूचना सं. 111/2002- सीमाशुल्क के तहत निश्चित पाटनरोधी शुल्क लगाया था।
5. प्राधिकारी ने दिनांक 29 मार्च 2004 को कोरिया गणराज्य और जर्मनी से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में मध्यावधिक समीक्षा जांच शुरु की और दिनांक 6 जून 2005 की अधिसूचना सं. 15/5/2004 के तहत कोरिया गणराज्य और जर्मनी से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चित पाटनरोधी शुल्क लगाना जारी रखने की सिफारिश की थी। दिनांक 1 सितम्बर 2005 की अधिसूचना सं. 78/2005-सीमाशुल्क के तहत सरकार द्वारा निश्चित पाटनरोधी शुल्क लगाया गया।
6. प्राधिकारी द्वारा दिनांक 4 को दूसरी निर्णायक समीक्षा जांच शुरु की गई और प्राधिकारी ने दिनांक 2007 अक्टूबर 8 की 2008 अक्टूबर अधिसूचना सं. 15/6/2007 के तहत कोरिया गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाना जारी रखने की सिफारिश की तथा दिनांक 2 जनवरी 2009 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 01/2009-सीमाशुल्क के तहत सरकार द्वारा निश्चित पाटनरोधी शुल्क लगाया गया।
7. प्राधिकारी ने दिनांक 31 दिसम्बर 2013 की अधिसूचना सं. 15/29/2013- डीजीएडी के तहत तीसरी निर्णायक समीक्षा जांच शुरु की। प्राधिकारी द्वारा दिनांक 30 जून 2015 की अधिसूचना सं. 15/29/2013- डीजीएडी के तहत अन्तिम जांच परिणाम अधिसूचना जारी की गई जिसमें कोरिया गणराज्य से आयातों पर निश्चित शुल्क लगाने की सिफारिश की गई। प्राधिकारी द्वारा अन्तिम जांच परिणामों में की गई सिफारिशों के आधार पर दिनांक 4 सितम्बर 2015 की अधिसूचना सं. 46/2015- सीमाशुल्क (एडीडी) के तहत दिनांक 4 सितम्बर 2020 तक वैध पाटनरोधी शुल्क लगाया गया।

विचाराधीन उत्पाद

8. मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद 'एक्रीलोनाइट्राइल बुटाडीन रबड़ (एनबीआर)' है। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की गई मूल जांच के अनुसार उत्पाद को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है:

'एनबीआर का प्रयोग विभिन्न रबड़ की वस्तुओं के ऐसे निर्माण में किया जाता है जहां पर तेल प्रतिरोधी, घर्षण और हीट अनुप्रयोग शामिल हों जैसे ऑयल सील, होज, ऑटोमेटिव उत्पाद, गास्केट, राइस डीहस्क़िंग रोल, प्रिंटर, फैब्रिक, ऑयलफील्ड उत्पाद इत्यादि। एनबीआर के लिए अपेक्षित मुख्य सामग्रियों में एक्रीलोनाइट्राइल और बुटाडीन हैं। एनबीआर के विभिन्न ग्रेड मूनिविस्कोसिटी और एक्रीलोनाइट्राइल कंटेंट के संदर्भ में परिभाषित किए गए हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं का प्रयोग संबद्ध देश से आयातित वस्तुओं के स्थान पर अदला बदली करके किया जाता है।'

9. चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है इसलिए विचाराधीन उत्पाद वही रहा जो पूर्व में की गई जांच में परिभाषित किया गया था।

10. आवेदक ने लेटेक्स एनबीआर, पावर एनबीआर और कारबोक्सिलेटेड एनबीआर को एनबीआर के दायरे बाहर करने का अनुरोध किया है। उत्पाद को उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की प्रथम अनुसूची के तहत अध्याय 40 के अन्तर्गत शीर्ष सं. के तहत और 40025900 आईटीसी एचएस वर्गीकरण के तहत वर्गीकृत किया गया है। तथापि यह कहा जाता है कि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह किसी भी रूप में उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

11. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध वस्तुएं, जो भारत में पाटित की जा रही हैं, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान हैं। पाटित वस्तुओं और घरेलू तौर पर उत्पादित संबद्ध वस्तुओं तथा आवेदक द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद के तकनीकी विनिर्देशन, गुणवत्ता, कार्य, अन्तिम उपयोगों में कोई अंतर नहीं है। तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से ये दोनों प्रतिस्थापनीय हैं और इसीलिए इन्हें नियमों के अनुसार “समान वस्तु” माना जाना चाहिए। अतः आवेदक द्वारा भारत में उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुओं के “समान वस्तु” माना जा रहा है।

घरेलू उद्योग

12. आवेदन मैसर्स एफ़ोटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने दावा किया है कि वह भारत में एनबीआर का एकमात्र उत्पादक है। आवेदक ने यह दावा किया है कि न तो संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है, और न ही वे संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक या उत्पादक से अथवा भारत में पीयूसी के किसी आयातक से संबंधित हैं। उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि आवेदन नियमावली के नियम 2 और (ख) नियम 5 में (3) निहित प्रावधानों के संदर्भ में “घरेलू उद्योग द्वारा और उसकी ओर से” किया गया है।

पाटन के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना

13. आवेदक ने यह दावा किया है कि कोरिया गणराज्य में प्रचलित कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सका। आवेदक ने नियमों के तहत निर्धारित वैकल्पिक तरीका अपनाया है जो कि कोरिया से तीसरे देश को निर्यात कीमत है। आवेदक ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए कोरिया से वियतनाम की निर्यात कीमत पर विचार किया है। कोरिया से वियतनाम के लिए विचाराधीन उत्पाद का महत्वपूर्ण निर्यात होता है और सूचना सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध है।
14. आवेदक ने सामान्य मूल्य के रूप में ट्रेड मैप डाटा के अनुसार कोरिया से वियतनाम को एफओबी निर्यात कीमत पर विचार किया है। संबद्ध मात्रा इस आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण और पर्याप्त है।
15. प्राधिकारी ने **वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय** डीजीसीआई एंड एस (के सौदा वार आयात डाटा के आधार पर संबद्ध देश के लिए निर्यात कीमत की गणना की है। समुद्री मालभाड़ा और समुद्री बीमा के संबंध में कीमत समायोजन किया गया है।
16. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत अनुमानों के आधार पर संबद्ध देश के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है। परिणामी पाटन मार्जिन महत्वपूर्ण है और नगण्य से काफी अधिक है। प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य निबल निर्यात मूल्य से अधिक है जो यह दर्शाता है कि संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुएं पाटित कीमतों पर निर्यात की जा रही हैं और इस प्रकार पाटन के जारी रहने का पता चलता है।

क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना

17. घरेलू उद्योग को मात्रात्मक प्रभाव की दृष्टि से अर्थात् संबद्ध देश से पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि और कीमत प्रभाव की दृष्टि से अर्थात् कीमत ह्रास के चलते नुकसान, लगाई गई पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल (आर ओ सी ई) और नकदी हानि को देखते हुए पाटन और उसके परिणामस्वरूप क्षति होने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं। इसके अलावा याचिकाकर्ता द्वारा अप्रयोज्य क्षमता, क्षमता विस्तार, कोरिया गणराज्य से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं पर चीन जन. गण. द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना भी प्रथम दृष्टया यह दर्शाता है कि पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने से घरेलू उद्योग को पाटन और उसके क्षति होने की संभावना है।

निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत

18. घरेलू उद्योग द्वारा और उसकी ओर से विधिवत पुष्ट लिखित आवेदन को देखते हुए और स्वयं संतुष्ट होकर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के बारे में, नियमावली के नियम 23 (1 ख) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार

प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में लागू पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की जरूरत की समीक्षा करने के लिए और यह जांचने के लिए कि क्या वर्तमान शुल्कों को समाप्त करने से घरेलू उद्योग को पाटन और उसके परिणामस्वरूप क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, एतद्वारा एक निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करते हैं।

संबद्ध देश

19. वर्तमान जांच में संबद्ध देश कोरिया गणराज्य है।

जांच की अवधि (पी ओ आई)

20. वर्तमान जांच में जांच की अवधि 1 अप्रैल 2019 से 31 दिसम्बर 2019 (9 माह) तक की है और क्षति अवधि में 1 अप्रैल, 2016 - 31 मार्च 2017, 1 अप्रैल, 2017 - 31 मार्च 2018, 1 अप्रैल, 2018 - 31 मार्च 2019 जांच की अवधि शामिल होगी।

प्रक्रिया

21. नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधानों को इस समीक्षा में आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू किया जाएगा।

सूचना प्रस्तुत करना

22. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों भारत में उनके दूतावास के, माध्यम से उनकी सरकार से संबंधित विचाराधीन उत्पाद, भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को अलग-दली अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे- गई समय सीमा में प्राधिकारी को निर्धारित प्रपत्र और तरीके में सभी संगत सूचना प्रस्तुत कर सकें।
23. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच के संबंध में नीचे दी गई समय सीमा में निर्दिष्ट प्रपत्र और तरीके से अपना अनुरोध भेज सकते हैं :

निर्दिष्ट प्राधिकारी
व्यापार उपचार महानिदेशालय
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5 संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001

24. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार से यह अनुरोध है कि वह अन्य पक्षकारों को उसका अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध करायें।

समयसीमा-

25. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित में दी जानी चाहिए ताकि वह नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी को पहुँच जाए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उपर्युक्त नियमावली की व्याख्या के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाए जाने संबंधी सूचना उस तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुई मानी जाएगी जिसको वह प्राधिकारी द्वारा भेजी गई थी अथवा निर्यातक देश के उपयुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधि को भेजी गई थी। यदि कोई सूचना निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होती है अथवा सूचना अपूर्ण प्राप्त होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकार्ड कर सकते हैं।
26. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपने हित (की प्रकृति सहित हितों) सूचित करें और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली के उत्तर दायर करें।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

27. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (परिशिष्ट/उससे संलग्न अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को, यदि उसके किसी भाग के संबंध में "गोपनीयता" का दावा किया गया है तो उसे दो अलग-अलग सेटों में दायर करना अपेक्षित है:

- i. गोपनीय के रूप में चिह्नित एक सेट (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, सूची आदि), और

- ii. अगोपनीय के रूप में चिन्हित दूसरा सेट (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, सूची आदि)।
28. "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" अनुरोध प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" के रूप में स्पष्ट रूप से चिन्हित होने चाहिए। इस प्रकार के चिन्हों के बिना किया गया कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी उन अनुरोधों का निरीक्षण करने के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अनुमति देने हेतु स्वतंत्र होंगे। दोनों रुपांतरों की सॉफ्ट प्रतियां भी प्रत्येक के चार सेटों की हार्ड प्रतियों के साथ प्रस्तुत की जानी अपेक्षित (4) होंगी।
29. गोपनीय रुपांतर में वह सभी सूचना होगी जो प्रकृति से गोपनीय और/अथवा अन्य सूचना है जिसको सूचना देने वाला गोपनीय होने का दावा करता है। जिस सूचना को प्रकृति से गोपनीय होने का दावा किया गया है अथवा जिस सूचना के संबंध में अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, उस सूचना के संबंध में सूचना देने वाले के लिए यह अपेक्षित है कि वे दी गई सूचना के साथ सही कारण का विवरण प्रदान करें कि उस सूचना का प्रकट क्यों नहीं किया जा सकता।
30. अगोपनीय रुपांतर को गोपनीय सूचना के साथ अधिमानतः उस सूचना के आधार पर सूचीबद्ध अथवा ब्लैंक आउट (यदि सूचीकरण व्यवहार्य नहीं है) तथा सारांश का प्रदर्श होना अपेक्षित है जिसके आधार पर गोपनीयता का दावा किया गया है। अगोपनीय सारांश गोपनीय आधार पर दी गई सूचना के सार की उपयुक्त समझ देने के लिए पर्याप्त ब्यौरे में होने चाहिए। तथापि, अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार यह दर्शा सकते हैं कि यह सूचना सारांश के लिए संवेदनशील नहीं है; सारांश क्यों संभव नहीं है, सका एक विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप दिया जाना चाहिए।
31. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा रद्द कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा यदि सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक करने का अनिच्छुक है अथवा सामान्य रूप में या सारांश रूप में उसे प्रकट करने के लिए प्राधिकृत नहीं करना चाहता तो वे उसकी अनदेखी कर सकते हैं।
32. किसी सार्थक अगोपनीय रुपांतर के बिना अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में अच्छे कारण के विवरण के बिना किया गया कोई अनुरोध प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।
33. प्राधिकारी संतुष्ट होने पर तथा दी गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता स्वीकार करने पर उस सूचना को प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसे प्रकट नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

34. नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार, कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रुपांतर से युक्त सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

असहयोग

35. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार सूचना देने से इंकार करता है अथवा अन्यथा उपयुक्त अवधि के भीतर आवश्यक सूचना प्रदान नहीं करता अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी उनके पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकार्ड कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को जैसा भी वे उचित समझें सिफारिश कर सकते हैं।

भूपिन्दर एस. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2020

Case No. SSR 04/2020

Sub: - Sunset Review of Anti Dumping Duty imposed on imports of Acrylonitrile Butadiene Rubber from Korea RP.

F. No. 7/5/2020-DGTR.—1. M/s Apcotex Industries Limited (hereinafter also referred to as the "Applicant") has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the

Authority), on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred as the “ Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the Rules), for Sunset Review of Anti-Dumping duty imposed on imports of “Acrylonitrile Butadiene Rubber” (hereinafter also referred as the “subject goods” or “product under consideration” or “PUC” or NBR) from Korea RP (hereinafter also referred to as the “subject country”).

2. The Applicant has alleged likelihood of continuation or recurrence of dumping of subject goods, originating and exported from the subject country and consequent injury to the domestic industry and has requested for review and continuation of the anti-dumping duty imposed on the imports of subject goods, originating in or exported from the subject country.

Background

3. The original investigation concerning imports of the subject goods from Korea RP and Germany was initiated by Authority vide Notification No. 9/1/95- ADD dated 15th March 1996. The Preliminary finding was issued by the Authority on 30th December 1996, recommending provisional antidumping duty on the imports of Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR) originating in or exported from Korea RP and Germany. The Authority notified its final findings on 17th July 1997 recommending definitive antidumping duty on the imports of NBR originating in or exported from Korea RP and Germany. The definitive antidumping duty (ADD) was imposed on the subject goods vide Customs Notification No. 62/1997-Customs, dated 30th July 1997.
4. The Authority had initiated a sunset review in the matter of continuation of final anti-dumping duty on acrylonitrile butadiene rubber originating in, or exported from Korea RP and Germany, and recommended continued imposition of definitive antidumping duty on imports of the subject good vide notification No. 50/1/2000 dated 21st September 2002. The definitive antidumping duty was imposed vide notification No. 111/2002-Customs, dated 10th October, 2002.
5. The Authority initiated mid-term review investigations on import of subject goods exported from Korea RP and Germany on 29th March, 2004 and recommended continued imposition of definitive antidumping duty on imports of the subject goods from Korea RP and Germany vide notification No. 15/5/2004 dated 6th June 2005. The definitive antidumping duty was imposed by Government vide Custom Notification No.78/2005-Customs dated 1st September, 2005.
6. The second sunset review investigation was initiated by the Authority on 8th October 2007 and the Authority recommended continued imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods from Korea RP vide Notification No. 15/6/2007 dated 4th October 2008. The definitive antidumping duty was imposed by Government vide Custom Notification No. 01/2009-Customs dated 2nd January 2009.
7. The Authority vide Notification No. 15/29/2013-DGAD Dated the 31st December 2013, initiated the third Sunset Review investigation. The Final Finding Notification was issued by the Authority vide Notification No. 15/29/2013-DGAD dated 30th June 2015, recommending imposition of definitive duty against imports from Korea RP. On the basis of recommendations made by the Authority in the final findings, definitive anti-dumping duty was imposed vide Notification No. 46/2015-Customs (ADD), 4th September 2015. The ADD is valid till 3rd September, 2020.

Product under consideration

8. The product under consideration as in the original investigation is Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR). As per the original investigation carried out by the Designated Authority, the product has been defined as under:

“NBR is used in the manufacture of various rubber articles where resistance to oil, abrasion and heat applications are involved, such as oil seals, hoses, automotive products, gaskets, rice de-husking rolls, printers, fabrics, oilfield products, etc. The major raw materials required for NBR are Acrylonitrile and Butadiene. Different grades of NBR are defined in terms of mooney viscosity and acrylonitrile content. The subject goods produced by domestic industry are used interchangeably with those imported from the subject country”

9. Since the present investigation is a sunset review investigation, product under consideration remains the same as defined in the previously conducted investigation.
10. The Applicant has requested for exclusion of Latex NBR, Powder NBR and Carboxylated NBR from the scope of NBR. The product is classified under heading No. 40025900 in Chapter 40 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975 and ITC HS Classification. It is however submitted that the customs classification is indicative only and in no way binding upon the product scope.

Like Article

11. The Applicant has claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods and the product under consideration manufactured by the applicant. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, the subject goods produced by the Applicant in India are being treated as 'Like Article' to the PUC being imported from the subject country.

Domestic industry

12. The application has been filed by M/s Apcotex Industries Limited. The Applicant has claimed to be the sole producer of NBR in India. The Applicant has also claimed that it has neither imported the subject goods from the subject country nor is related to any exporter or producer of subject goods in the subject country or any importer of the PUC in India. On the basis of information available, the Authority is satisfied that the Application has been made 'by or on behalf of the domestic industry' in terms of the provisions contained in Rule 2 (b) and Rule 5 (3) of the Rules.

Likelihood of continuation or recurrence of dumping

13. The Applicant has claimed that Normal Value could not be determined on the basis of prevailing prices in Korea RP. The Applicant has adopted the alternative method prescribed under the Rules, that is, export price from Korea to a third country. The Applicant has considered export price from Korea to Vietnam for determination of Normal Value. There are significant exports of the product under consideration from Korea to Vietnam and the information is publicly available.
14. The Applicant has considered FOB export price from Korea to Vietnam, as per Trade Map data as Normal Value. The associated volumes are significant and sufficient to enable determination of Normal Value on this basis.
15. The Authority has computed the export price for the subject country on the basis of the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S), transaction-wise import data. Price adjustments have been made on account of ocean freight and marine insurance.
16. Dumping margin has been determined for the subject country considering the estimates of Normal Value and export price. The resultant dumping margin is significant and much above de-minimus limit. There is prima facie evidence that Normal Value of the subject goods in the subject country is significantly higher than the net export price, indicating that the subject goods originating in or exported from the subject country are being exported at dumped prices, thus indicating likelihood of continuation of dumping.

Likelihood of continuation or recurrence Injury

17. There is prima facie evidence of dumping and consequent injury to the domestic industry on account of volume effect, that is, increase in volume of dumped imports from subject country and price effect, that is, price suppression, leading to losses, negative return on capital employed (ROCE) and cash losses. Further, the data provided by the Applicant regarding unutilized capacity, capacity expansions, imposition of anti-dumping duty by China PR on subject goods exported from Korea RP also prima facie indicates a likelihood of dumping and injury to domestic industry on cessation of the ADD.

Initiation of Sunset Review Investigation

18. On the basis of the duly substantiated written application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, about the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry, in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23(1B) of the Rules, the Authority, hereby, initiates a Sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of existing ADD duties are likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the Domestic Industry.

Subject Country

19. The subject country in the present investigation is Korea RP.

Period of Investigation (POI)

20. The period of investigation (POI) for the present investigation is 1st April, 2019 to 31st December, 2019 (9 months) and the injury period will cover the period of 1st April, 2016-31st March 2017, 1st April, 2017-31st March 2018, 1st April, 2018-31st March 2019 and the POI.

Procedure

21. The provisions of Rule 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules shall be mutatis mutandis applicable in the present investigation.

Submission of Information

22. The known exporters in the subject countries, their Government through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the PUC and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
23. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below. The information/ submission may be submitted to:

The Designated Authority**Directorate General of Trade Remedies****Department of Commerce****Ministry of Commerce and Industry****4th Floor, Jeevan Tara Building****5, Parliament Street, New Delhi – 110001**

24. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time Limit

25. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting Country. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
26. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

Submission of Information on Confidential Basis

27. The parties making any submission (including Appendices/Annexes attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:
- one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and
 - the other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).
28. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies in four (4) sets of each.
29. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
30. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

31. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
32. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
33. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

34. In terms of rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidences submitted by other interested parties.

Non-Cooperation

35. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

BHUPINDER S. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority